

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2130 / 2011 / चित्तौड़गढ़.

मैसर्स मंगलम् मार्बल्स प्रा0 लिमिटेड, चित्तौड़गढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 29 / 4 / 2014**

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 44/वेट/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.8.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2007-08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 19.7.2010 की पुष्टि की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के दौरान मार्बल की गैंगसा मशीनों पर जॉब वर्क के तहत निष्पादित किये गये कार्य हेतु राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये डायमण्ड सेगमेंट एवं ब्लेड्स पर चुकाये गये वेट क्रमशः रुपये 22,487/- का आई.टी.सी. चाहा गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2011 से अस्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवहारी मार्किनिंग के साथ विनिर्माता एवं व्यवसायी भी है। अधिनियम की धारा 18(1) के तहत व्यवहारी आलौच्य अवधि के दौरान जॉबवर्क के लिये उपयोग में लिये गये डायमण्ड सेगमेंट एवं ब्लेड्स पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. क्लेम करने के अधिकारी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के मार्बल ब्लॉक की चिराई कर स्लेब तैयार करने एवं जॉब वर्क हेतु क्रय किये डायमण्ड सेगमेंट एवं ब्लेड्स पर अदा किये गये वेट का आगत कर क्लेम अस्वीकार करने में भारी भूल की गई है। अग्रिम कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि किसी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगत कर क्लेम तभी देय है, जब राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से करयोग्य माल खरीद कर उससे नवीन वस्तु का निर्माण कर पुनः कर योग्य माल के रूप में विक्रय करता है अथवा कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में खरीद कर उससे निर्मित नयी वस्तु राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय/निर्यात करता है अथवा कर योग्य माल खरीद कर राज्य में केपिटल गुड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये विवादित माल का उपयोग जॉबवर्क में एवं अपना माल चिराई में किया गया है, इस प्रकार इससे कोई पृथक व विशिष्ट वस्तु का निर्माण किया जाकर पुनर्विक्रय नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित माल को अपीलार्थी का केपिटल गुड्स भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि डायमण्ड सेगमेंट्स एवं ब्लेड्स कन्ज्यूमेबल आईटम्स हैं, जो मार्बल चिराई के दौरान समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्लांट एवं मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए भी अधिनियम की धारा 18 के तहत इन पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

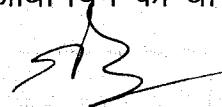
उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान डायमण्ड सेगमेंट एवं ब्लेड्स का वेट चुकाकर क्रय किया गया है एवं उक्त माल का अन्य फर्मों से प्राप्त जॉबवर्क के निष्पादन के लिये मार्बल स्लेब के निर्माण हेतु उपयोग किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने विवादित आईटम पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.7.2010 द्वारा व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आगत कर को अस्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा :-

### 18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (f) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

अधिनियम की धारा 18(1) के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी द्वारा कर चुकाकर कच्चे माल के रूप में क्रय किये गये माल का विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नवीन वस्तु का निर्माण कर, कर योग्य माल के रूप में विक्रय किये जाने की स्थिति में ही चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय किया गया है। उक्त प्रावधानों से यह कतई स्पष्ट नहीं होता कि जॉबवर्क के निष्पादन में प्रयुक्त कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञात किया जावेगा। इस सम्बन्ध में केपीटल गुड्स की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(7) स्पष्ट है :-

 लगातार.....4

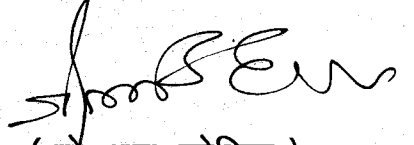
2(7) - "capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;

**Explanation-**For removal of doubts, it is hereby clarified that "capital goods" do not include any equipments or appliances used in an office of a dealer or used in execution of works contract.

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये विवादित माल का कर योग्य माल के रूप में पुनर्विक्रय किया जाना भी नहीं पाया जाता है तथा माल केपीटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आना पाया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सीमा तक अपीलार्थी व्यवहारी का आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
29/11/14